[Shri Pranab Kumar Mukherjee]

sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Nagaland for the services of the financial year 1975-76, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Nagaland for the services of the financial year 1975-76, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, we take up clause by clause consideration.

The question is:

"That Clauses 2 and 3 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 and the Scheduled were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is.

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: I move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.02 hrs.

MOTION *RE*: ALLEGED VICTIMISATION OF EMPLOYEES OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) सभापति महोदय, में प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कर्मचारियों के कथित उत्पीड़न और आल इंडिया फेडरेशन आफ एम्पलाईज की मान्यता वापस लेने के निर्णय के सम्बन्ध में वित्त मंत्री द्वारा 22 अगस्त, 1974 को सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

वित्त मंत्री का वक्तव्य 22 अगस्त को दिया गया था, मगर उस पर विचार करने का अवसर इस सदन को इतने महीनों के बाद आज 8 मई को प्राप्त हुआ है। यह कहना होगा कि यह सदन अपने कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं है।

संविधान के अन्तर्गत कंट्रोलर एण्ड आडिटर जेनेरल का एक विशिष्ट स्थान है। उन के ऊपर लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन की सहायता के लिए सारे देश में हजारों कर्मचारी तैनात हैं। क्या यह आवश्यक नहीं है कि उन कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए, और उचित शिकायतों का निराकरण करने के लिये, कोई तंत्र हो ? आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि जो जायंट कनसल्टेटिव मशीनरी केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों में चल रही है, जिस के अन्तर्गत विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मिल कर, बैठ कर, अपनी समस्याएं हल करते हैं, शिकायतें दूर करते हैं, वह व्यवस्था कंट्रोलर एण्ड आडिटर जेनेरल के विभिन्न दफ्तरों में कार्यरत नहीं है।

1968 से डिपार्टमेंटल कौंसिल मृत पड़ी है। उसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयत्न कर्मचारियों की ओर से किये गये। लेकिन कंट्रोलर एण्ड आडिटर जैनेरल ने कोई अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

अगर कर्मचारियों को अपनी शिकायतें रखने का मौका नहीं मिलेगा, उन को विचार विनिमय का अवसर प्राप्त नहीं होगा, तो फिर उन में असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बढ़ती हुई महंगाई उस के अनुरूप भत्ता देने में सरकार की विफलता, नये वेतन मानों की मांग और दिन-प्रति दिन के कार्य में सुविधाओं का अभाव, ये ऐसे प्रश्न हैं, जो कर्मचारियों को आन्दोलित करते रहते हैं। लेकिन कंट्रोलर एण्ड आडिटर जैनेरल महोदय और उन के अन्तर्गत अधिकारी कान बन्द कर के बैठे हैं।

मुझे अफसोस है कि इस चर्चा के दौरान वित्त मंत्री सदन में नहीं है। मैं अपने मित्र, श्री प्रणव मुखर्जी, का आदर करता हूं। मगर यह कंट्रोलर एण्ड आडिटर जैनेरल का मामला इस स्तर पर तय होगा, इस की मुझे आशा नहीं है। मैं किसी को उद्धृत नहीं करना चाहता हूं, मगर मुझे यह कहा गया है कि अगर आप कंट्रोलर एण्ड आडिटर जैनेरल के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ न्याय, कराना चाहते हैं, तो प्रधान मंत्री का दरवाजा खटखटाइये, उन के नीचे कोई बात नहीं सुनेगा।

क्या कंट्रोलर एण्ड आडिटर जैनेरल कोई तानाशाह है? क्या वह मनमानी करने की छूट रखते हैं? शासन-व्यवस्था में जो नियम, जो नीतियां और जो निर्णय अन्य विभागों में लागू होते हैं, क्या वे कंट्रोलर एण्ड आडिटर जैनेरल के कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे?

10 मई को कंट्रोलर एण्ड आडिटर जैनेरल के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल की। उस से पहले पेन-डाउन स्ट्राइक हुई थी। लेकिन हड़ताल एक दिन की थी। हड़ताल मुख्य रूप से नये वेतन-मानों की मांग को ले कर, और रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से सहानुभूति प्रकट करने के लिए हुई थी।

क्या यह आश्चर्य नहीं है कि जिन रेल कर्मचारियों ने हड़ताल की, उन में से जिन कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा और तोड़ फोड़ के आरोप थे, उन को छोड़ कर बाकी के सभी कर्मचारी प्राय वापस ले लिये गये हैं? रेल बजट प्रस्तुत करते हुए रेल मंत्री ने घोषणा की कि किसी की सेवा में भंग नहीं होगा और कर्मचारियों के साथ न्याय किया जायेगा। रेल की हड़ताल करने वाले कर्मचारी वापस ले लिये गये, मगर उन की सहानुभूति में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने वाले कंट्रोलर एण्ड आडिटर जैनेरल के कर्मचारी नौकरी से निकाल दिये गये।

इस बारे में आंकड़े क्या हैं? डी० आई० आर० के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, उन की संख्या 55 है, जिन में से ग्वालियर के 32, त्रिवेंद्रम के 15 और राजकोट के 8 हैं।

श्री शंकर देव (बीदर) उन्होंने शायद हड़ताल करने वालों की सहानुभूति में तोड़ फोड़ की होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी शंकर जी महाराज जा कर मुनि सुशील कुमार की प्रशंसा में प्रवचन करें। उन को तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है। वह बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हैं।

कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई। और आडिट आफिस में तोड़-फोड़ क्या होगी? कर्मचारी काम पर नहीं गये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कलम तोड़े होंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कलम तोड़ने की भी घटना नहीं हुई। कलम बन्द करने की घटना पहले हुई थी।

डी० आई० आर० का क्या मतलब है ? आपको स्मरण होगा कि हमने जब 4-12-71 को डी० आई० आर० का कानून पास किया था, तो कहा गया था कि वह किन बातों पर लागू होगा। मुख्य रूप से पाच बातें थी :-

(i) Defence of India

(ii) Civil Defence.

(iii) Maintenance of public order and safety.

(iv) Efficient conduct of military operations.

(v) Maintenance of supplies and services which are essential to the life of the community

मगर इससे आडिट का क्या सबंध है ? अगर दो दिन आडिट का काम न हो, तो क्या नागरिक जीवन अस्त व्यस्त हो जायगा, युद्ध प्रयत्नो मे बाधा पड जायगी, शत्रु की सेनाएँ भारत मे प्रवेश कर जायेगी ? कैसी हास्यस्पद बात है। आडिट सेवा को किसी भी कसौटी से अनिवार्य सेवा नही कहा जा सकता है ? लेकिन मान लीजिये कि डी० आई० आर० लगा दिया गया, मगर जब और विभागो मे डी० आई० आर० के केसिज वापस ले लिये गये है, तो फिर कन्ट्रोलर एंड आडिटर जैनरल के कर्मचारियो के साथ ही यह अन्याय क्यो किया जा रहा है ?

जो कर्मचारी नौकरी से निकाले गये हैं उनकी संख्या 48 है। जो सुस्पेन्ड किये गये है, उनकी संख्या 72 है। 12,000 कर्मचारियों का ब्रेक इन सर्विस है, जिसमे वेज कट भी शामिल है। हड़ताल हुई थी 10 मई को। 11 और 12 मई को छुट्टी थी-दूसरा शनिवार और इतवार था, मगर उन दिनों की भी तनख्वाह काट ली गई। यह अंधेरगर्दी है या संसदीय लोकतंत्र है ?

तनख्वाह काटने के बारे मे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कबिनेट सैक्रेटेरियट के डिपार्टमेंट आफ पर्सोनिल से पूछा था कि क्या 11 और 12 मई की तनख्वाह काटी जाय। उन्होने स्पष्टीकरण दे दिया कि 11 और 12 मई को सार्वजनिक छुट्टी थी, इसलिये उन दिनो के वेतन की कटौती नही होनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कटौती की थी, उसने उसको पूरा कर दिया लेकिन वह निर्णय ए० जी० आफिस पर लागू नही होता है। यह सरकार एक है या टुकडो से बटी है।

हड़ताल एक अन्तिम हथियार है। हड़ताल हो या न हो, इसके बारे मे मतभेद हो सकता है। लेकिन हड़ताली कर्मचारियो से निबटने के लिये हम अलग अलग मापदड तो नही अपना सकते। आपको याद होगा कि गोदी कर्मचारियो ने हड़ताल की थी। उनके साथ समझोते की वार्ता हुई और रास्ता निकाला गया। अभी 13-3-75 को इंडियन आयल कार्पोरेशन के एम्प्लाईज ने पेन-डाउन स्ट्राइक की। उनके साथ भी बात चीत करके हमने उनकी उचित शिकायते दूर करने का प्रयत्न किया। फिर आडिट कार्यालयो मे काम करने वाले कर्मचारियो ने ऐसा कौन सा पाप कियाहै, जिस की सजा उन्हे जीवन भर भुगतनी पड़ेगी ?

हड़ताल के दौरान क्या हुआ, इस संबंध मे दो उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे अधिक उत्पीडन ग्वालियर मे हुआ है। ग्वालियर मेरे चुनाव क्षेत्र का केन्द्र है। शायद ग्वालियर का यही अभिशाप है कि उसने मुझे प्रतिनिधि के रूप मे चुन कर इस सदन मे भेजा है। ग्वालियर में पुलिस ने जैसा जुल्म किया, उसकी कोई मिसाल नही है

8 मई को आडिट के दो कर्मचारी श्री राधुलाल शर्मा और श्री आर० के० बंसल, रेलवे स्टेशन पर गये थे । उन्हें रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया । आडिट सप्लाई के आन्दोलन से उस समय कोई संबंध नहीं था । क्या रेल कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना भी कोई जुर्म है ?

9 मई को कर्मचारियों को घरों में घुस कर गिरफ्तार किया गया । औरतों और बच्चों को अपमानित किया गया । उसी दिन 92 कर्मचारी ए० जी० दफ्तर के सामने पकड़े गये । वे शान्तिपूर्ण ढंग से दफ्तर में न जाने के लिये कह रहे थे । पुलिस ने उनको पीटा । 10 मई को भी गिरफ्तारियां हुई ।

जो कर्मचारी नौकरी से निकाले गये, उनकी मदद के लिये सब कर्मचारियों से रुपया इकट्ठा करना क्या कोई अपराध है ? 15 जून को उन लोगों की सहानुभूति में एक सभा करने के लिये श्री दिवाकर शर्मा को घर से रात के 2 बजे पकड़ा गया । आडिट के कर्मचारी को हथकडी डाल कर बाजार में घुमाया गया । यह तो हम ने स्मगलरों के साथ भी नहीं किया है । तस्करों को संरक्षण देने वाली सरकार अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करे, यह शोभा नहीं देता है ।

पैसा इकट्ठा करने के जुर्म मे अभी तक ग्वालियर में दो कर्मचारी निकाले जा चुके हैं—श्री बुबे और श्री बंगाली बाबू । उनका यही जुर्म था कि जो लोग नौकरी से निकाले गये, उनके बीबी बच्चों के पालन के लिये उन्होंने और कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा किया । इस देश मे अब यह भी जुर्म हो गया है ।

राजकोट में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था । मुझे अफसोस है कि पुराने वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन में गलतबयानी की । उन्होंने कहा कि राजकोट में इनटिमिडेशन और वायलेंस हुआ । मेरे पास पुलिस द्वारा दी गई चार्जशीट की नकल है । उस में इनटिमिडेशन या वायलेंस का कहीं भी जिक्र नहीं है । उस में इतना कहा गया है कि उन्होंने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया था, और शान्तिपूर्ण प्रदर्शन इस लिए किया था कि एक कर्मचारी को मुअत्तिल कर दिया गया था । 4-30 या 5-30 बजे तक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुआ । डिफेंस आफ़ इंडिया रूल्ज को लागू कर दिया गया, कर्मचारियों को गिरफ़्तार कर लिया गया और नौकरी से निकाल दिया गया । वहां आंतक का वातावरण पैदा कर दिया गया । ट्रिवेड्रम मे भी ऐसा ही हुआ है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों के बारे में क्या होने जा रहा है । क्या सदन असहाय है ? क्या इस सदन के सम्मानित सदस्य इन कर्मचारियो को न्याय दिलाने की स्थिति में नही हैं ? क्या यह सरकार हाथ रख कर बैठी रहेगी ? क्या कर्मचारियों को मरने दिया जायेगा ? क्या कंट्रोलर एंड आडिटर जैनेरल को मनमाने ढंग से आचरण करने की छूट होगी ? आखिर इस सरकार की कर्मचारियों से निबटने की, श्रम के साथ व्यवहार करने की, एक नीति होगी या नहीं ? कंट्रोलर एंड आडिटर जैनेरल उस नीति के अन्तर्गत आयेंगे या नहीं ? वह एम्पलाईज की कोई कनसल्टेटिव कौसिल बनायेंगे या नहीं ?

रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की, मगर आल-इंडिया रेलवेमैन्ज फ़ैडरेशन की, जिस ने हड़ताल का नोटिस दिया था, मान्यता वापस नहीं ली गई । मगर कंट्रोलर एंड आडिटर जैनेरल ऐसे हैं कि उन्होंने एम्पलाईज फैडरेशन को तो काज नोटिस दे दिया कि बताओ, तुम्हारी मान्यता क्यों न वापस ले ली जाये । रेलवे में वह यह नहीं हुआ है । रेलवे की सेवायें आवश्यक सेवायें हैं ; उन के भंग होने से समाज का जीवन अस्त-व्यस्त होने की आशंका

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

लेकिन वहां फ़ेडरेशन को तो कोई नोटिस नहीं दिया गया, जब कि ए० जी० आफ़िस की फ़ेडरेशन को नोटिस दे दिया गया ।

कर्मचारी फ़ेडरेशन ने उस नोटिस का जवाब दे दिया, मगर अब कंट्रोलर एंड आडिटर जेनेरल चुपी साध कर बैठे है । तो काज नोटिस अभी तक कायम है । कर्मचारियों से कोई बात नहीं हो रही है । कर्मचारी दफ़्तर के बाहर मीटिंग नहीं कर सकते । वे डरे हुए है, भयभीत है । किस पर फ़ासिज्म का आरोप लगाया जा रहा है ? क्या लोकतंत्र मे कर्मचारी अपनी उचित शिकायतें शांतिपूर्ण ढंग से नहीं रख सकेंगे ? क्या उन की शिकायतों पर विचार करने के लिए कोई तंत्र नहीं होगा ?

मैं इस मामले मे बहुत दुखी हूं । रेलवे कर्मचारियों के लिए सदन ने आवाज उठाई, सरकार ने सुना और रेल मंत्री ने सहानुभूति से विचार करने का आश्वासन दिया । मगर आडिट एम्पलईज के लिए कोई सुनने को तैयार नहीं है ।

मैं कोई कठोर बात नहीं कहना चाहता । लेकिन आज अगर मंत्री महोदय की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर न दिया गया, तो कर्मचारी संघर्ष करे या न करे, उन के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा और मै कोई ऐसा कदम उठाऊंगा जो मैं उठाना नहीं चाहता ।

मगर हम कब तक यह बर्दाश्त करते रहेंगे? आज तक की चर्चा के लिए मै रुका था । श्री मुकर्जी की कठिनाई मैं जानता हूं । देखें कि वह क्या उत्तर देते है । मैं आशा करता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य उन उत्पीड़ित कर्मचारियों के पक्ष मे अपनी आवाज उठायेंगे और जो कानों में रुई डाले बैठे है, उन तक उन के दुख दर्द को पहुंचाएंगे, अन्यथा अगर असंतोष भीतर ही भीतर घुमड़ेगा, तो कभी भी विस्फोट का रूप ले कर फूट पड़ेगा ।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That this House do consider the statement made by the Minister of Finance in the House on the 22nd August, 1974 regarding the alleged victimisation of the Employees of the Comptroller and Auditor General and the decision to withdraw the recognition from the All India Federation of Employees".

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Seerampore): Sir, I fully support and join my voice with Shri Vajpayee who has very ably put the longstanding cases of the employees of the Audit and Accounts Department throughout India.

My first point is this. I want to know whether the Government have ever declared the employees of the Auditor General's Office as essential services. If they have not done so, how can they apply D.I.R. against the employees? The statement about which Shri Vajpayee has also mentioned was a misleading statement made by the Finance Minister. He said in his statement that the employees who have been arrested and victimised committed violence. Shri Vajpayee has given example. I have also got the copies of F.I.R. and chargesheets given by the police. In Rajkot, nine employees were prosecuted. But, nowhere you will find the charge of violence. They simply shouted slogans and they joined the strike. These are the offences for which they had been arrested and detailed under D.I.R. D.I.R. has been misused in this way in the case of the employees.

Sir, this is a very important department in all respects. Even the Administrative Reforms Commission has stated that it is a watchdog of our finances. Ever since the existing Auditor-General came to hold that Office, the trouble started.

Before that there were good relations between the management and

the employees but since this gentleman took over, he marrily goes on with the autocratic actions as he is appointed by the President and there is no body to check him in any way. The employees have repeatedly given representations and have also approached the Central authority but nothing has been done uptil now.

I learn that till today 6,000 employees are suffering from break in service. Is it true or not? If not, please supply us the total number of employees in whose case there is break in service or who have been suspended or whose services have been terminated. Please inform the House as to what the Government is going to do, so that normalcy in this Department throughout the country may be restored. As Mr. Vajpayee has also pointed out there is no minimum right of functioning as a member of the Employees' Association there. Why is it so? In other departments of the Government the employees have the right to function constitutionally as a representative of the Association. A show-cause notice was issued to this Association and it was practically de-recognised. I ask why an opportunity for dialogue and negotiation on matters relating to employees is denied to them. Government has taken a decision in respect of railway employees. These employees also went on strike in support of the Railwaymen strike on 10th May. On 11th and 12th May, there were holidays. On 13th they withdrew from the strike. I do not understand why the Government has not so far been able to decide to restore the two-days (11th and 12th May, 1974) wage cut to these poor employees.

At the present moment there is functioning joint machinery for negotiation in other departments. There was such a machinery in the Audit department also but as Mr. Vajpayee has pointed out it was practically disbanded during 1968 to 1970. After that again the functioning of that negotiating machinery started.

But, after this token strike, this machinery has been completely made infructuous. All the doors have been closed down. There is no way of negotiation on any matter. Whatever importance they may have, they have no scope to place their grievances before the authorities. Therefore, this attitude must be checked immediately. Sir, this is a very important thing.

MR. CHAIRMAN: Go ahead. But, do not repeat the point.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: No question of repeating. But, this is very important. Why should they not hear the employees' grievances? Where will they go? There is no system, there is no way out and there is no channel to approach the authorities. The grievances may or may not be acceptable to the authorities, but, at least, they must have the opportunity to put the demands before the concerned authorities. They have already issued the show cause notices for derecognition of the Association of the Audit Employees. Why don't you end it here and now? Let this association function constitutionally and let them have a full say on any matter concerning the grievances of the employees as a whole.

Now, some victimisation has already taken place. Over and above break in service, suspension and termination of service, you have debarred them from appearing in any examination for any promotion. In the name of loyal employees, the claims of the regular employees are being superseded by that of the junior employees. This is the policy of divide and rule. Twentyseven thousand employees participated in the strike. They are not even allowed to cross the efficiency bar. Their increment is also stopped. The general increment, usual increment, is stopped in

an illegal way. They are not even allowed to send any deputation for any purpose or for meeting any authority so that they may put forward their claims before particular authority. They are not allowed to appear in any all India competitive examination or in any interview for appointment to any higher post in any other department. But, the other employees of other Government departments have the privilege to appear in certain examinations for promotion and better chances in any other department. Here, in the case of the Accounts Department, you have snatched the privilege. All these things are continuing and the Government is keeping silent for what reasons, I do not know. This has been again and again raised here; several times. His senior colleague made a statement here. His statement was mis-leading. He must clarify. Where is the charge of violence against persons against whom cases are still pending in Rajkot and other places? I have got a copy. No charge of violence against anybody. Shouting cannot be a charge of violence, participation in the strike cannot be a charge of violence or asking the colleagues to join the strike cannot be a charge of violence. The Finance Minister made a statement here in the House giving a mis-leading impression that they are committing violence The Government have to clarify that. The second point is, whether the rights that they were enjoying prior to the strike will be restored or not, whether the so-called notice on the association will be withdrawn or not and whether they will have the minimum right to function in the association just like the employees of other Government departments?

So he must clarify the point that I raised.

Lastly, I would plead with him to kindly see that normalcy comes back and the case against employees who have been victimised either in the form of termination of service, or in the form of break in service or in the form of suspension or in some other form are immediately withdrawn so that there way not be any grievance on the part of these employees that inspite of the issues being raised in the Parliament the Government made no justice to them.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I congratulate my hon friend, Shri Vajpayee, on bringing this motion before the House. We have been trying since the last six or seven months to bring it up here, but every time something has come in between; sometime it is Tulmohan Ram, some other time it is Jayaprakashji our respected leader Somebody came in the way with the result that this discussion did not take place Now on the last but one day of this session—we are adjourning tomorrow—at least this discussion has come up before the House.

As far the employees of this particular department, headed by the all powerful Comptroller and Auditor General Shri Bakshi, for whom I have the greatest regard, 15 in Trivandrum, 33 in Gwalior and 9 in Rajkot are being prosecuted under Rule 119 (a) and (b) of DIR, although this particular department was not declared as essential service after the strike took place Because it was not declared an essential service, I do not know how they brought it under DIR. In regard to other departments, all the cases practically, with the exception of a very few, have been withdrawn in the railway department As for other departments like P & T and income-tax, all the staff who went on strike have been taken back.

The strike took place on the 10th May. The 11th was a second Saturday and 12th Sunday. It was withdrawn on the 13th May, an announcement to

this effect being made on the 12th itself. There were 5 terminations in the income-tax department, 22 in Printing & Stationery and about 40 in the P & T department. All of them have been taken back. The number of suspended employees in all other departments (excluding Railways) is less than those in the audit department alone.

Surprisingly nobody has been taken back. In Gwalior, I met some of these victimised employees. They told me that they were beaten mercilessly, their family members were tortured. Even among the railway employees, some of them were not tortured to this extent as the employees in Gwalior and in Rajkot. There was no question of violence. The charge against them was that they shouted slogans. If shouting of slogans is violence or intimidation, then Shri Stephen should be put behind bars because he is shouting here from morning till evening.

Break in service was imposed on 12,000 employees out of the total of 27,000 employees. Even today it has not been regularised in respect of 6,000 of them.

What are their disabilities? They are debarred once from appearing in the departmental examinations. There is no permanent negotiating machinery functioning. There is no JCM functioning. All facilities to the Association have been withdrawn. In regard to the railwaymen's strike, the All India Railwaymen's Federation have not lost their recognition I am happy about it.

They have not been debarred. They are having the PNM. The Comptroller and Auditor-General, the CAG enjoys a peculiar position under the Constitution. He has actually dealt with them shabbily. Article 148(1) of the Constitution says:

"There shall be a Comptroller and Auditor-General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court."

Both the Houses have to be consulted if he has to be removed. He holds office under the pleasure of the President. When Mr. Giri was the President, he did say that those persons should also be taken back along with the railway employees. When Shri Chavan was Finance Minister, he made a conciliatory statement in response to a call attention notice or under 377 from me, Shri Limaye and Shri Vajpayee and he said: please wait. He was having some talk with the CAG. In 1960 the audit people went on strike. At that time A Roy was the CAG and Morarji Desai was the Finance Minister. All those people were taken back. Mr. E. h Joseph one of the heroes and leader of the audit employees, was also reinstated. In 1968 when the strike took place Shri Ranganathan was the CAG and he did not resist their reinstatement. The resistauce of the present CAG Bakshi, is the fust instance; he refuses to recognise the union; he refuses to talk to them. On every matter they have to demonstrate. I congratulate the audit employees through out the country for having the courage to fight this autocrat. The Prime Minister should intervene and the Government should give an assurance that whatever is applicable to the railway employees should be applicable to the audit employees. Shri Vajpayee said that if the Government did not give a satisfactory reply, he would ask them to start an all India agitation. He feels so bad about it. As a victimised employee, I know what is happening in Allahabad and other places. The A. G. of that particular place is behaving like a Hitler and is trying to victimise all those who are working there. He may occupy a peculiar position under the Constitution; still the CAG is a creature of

[Shri S. M. Banerjee]

the Constitution and he should be summoned here in this House and he should be impeached according to the provisions of the Constitution, unless things are set right. We cannot tolerate this situation any more. The time has come when Shri P. K. Mukherjee should act with the courage of his conviction. The CAG is not above law. He must realise his position I hope the hon. Minister will give a satisfactory answer to the questions raised.

श्री राम सहाय पांडे (रानन्दगाव) : सभापति महोदय,

सभापति महोदय जरा थोड़े में बोलिये एक-दो दूसरे लोग भी बोलना चाहते है और मिनिस्टर साहब को भी जवाब देना है।

श्री राम सहाय पांडे सभापति महोदय, काम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जैनरल के दफ्तर के कर्मचारियों की हड़ताल पर श्री वाजपेयी जी ने जो सवेदना प्रकट की, उन की भावनाओं को मैं बहुत इज्जत करता हू। श्रमशील समाज के प्रति, श्रमिकों के प्रति हमारी हमदर्दी सदैव रहती है। सदन की भी और पार्टी की भी। केवल दृष्टिकोण का अन्तर हो सकता है। लेकिन जहा तक सहानुभूति की बात है, जहा तक उस को लाभान्वित करने की बात है, उन को कोई कष्ट न पहुंचे, वहा तक कोई मतभेद नही है। लेकिन बात कहा से कहा बनती है। रेलवे की हड़ताल हुई, रेलवे जनता की सेवा का प्रतिष्ठान है, उस से इस का कोई सम्बन्ध नही है। इस में काम करने वाले लोग बाबू हैं आप। हम जानते हैं कि उनके भी अपने हक हैं, उस के प्रति हम जाग रूक है, सहानुभूति रखते है। लेकिन रेलवे जो पब्लिक यूटिलिटी कन्सर्न है उससे यह जुड़ गया, यह बहुत कुछ उचित बात नही है। उन की अपनी मांग है तीसरे पे कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार जिस मे यह राय दी गई की कि 330–550 रु० का वेतन-मान.

सभापति महोदय : आप का मतलब है कि कोली दामन का नाता नही है।

श्री राम सहाय पांडे : जी हा। कोई औचित्य नही है। यह बाबू लोग हैं, कलम पकड़ हड़ताल कर सकते है, वह मजदूर नही हैं जो फैक्ट्रियो मे काम करते है। लेकिन इन की भी आवश्यकतायें हैं। वेतन-मान अगर कम है तो सोचा जा सकता है। तो तीसरे पे कमीशन के अनुसार 330–550 के वेतन-मान से असतोष बढ़ा। और लोकतंत्र मे असतोष की अभिव्यक्ति हड़ताल हो सकती है, कलम पकड़ हड़ताल हो सकती है बाहर निकलने को, न काम करने को हड़ताल हो सकती है। उस मे 12,000 लोगो को सर्विस मे ब्रेक आया, 18 को निकाल देना, और 72 को सस्पेंड कर देना, मै सरकार से कहूगा कि वह इस बारे मे सहानुभूति से सोचे।

मै इन की हड़ताल को मजदूरो की हड़ताल से भिन्न मानता हू क्यो कि इन के उपर परिवार का ज्यादा दायित्व होता है। उस का कारण यह है कि मजदूर के परिवार मे दो, तीन आदमी काम करते है, और इन बाबू लोगों के यहा एक ही आदमी काम करता है इसलिये परिवार का दायित्व ज्यादा है। जैसा वाजपेयी जी ने कहा कि रेलवे की हड़ताल समाप्त होने के बाद हिंसा करने वालो को छोड़ कर, जैसे आप ने सब को ले लिया, वैसे ही इन को भी ले लीजिये। इस से एक अच्छा वातावरण बन सकेगा जिस मे हड़ताल की प्रवृत्ति भी कम होगी।

मेरा ऐसा विचार है कि विरोधी दलो के लोगो का काम करने का एक मापदंड होना चाहिये। जैसी हमारी आर्थिक स्थिति है वह अच्छी नही है, और साथ ही आप इनफ्लेशन की भी शिकायत करते हैं। इसलिये नोट छाप कर आप कीमतो को नीचे नही ला सकते। इस सम्बन्ध मे कही न कही कोई संकल्प, कोई लक्ष्मण रेखा खीचनी पड़ेगी जहां पर आप उन की सहायता करे, सहानुभूति प्रकट करें, उन को ऊपर भी उठाये, जीवन की धारा के साथ

उन को भी लायें। लेकिन नोट छापने की स्थिति पैदा न हो जिस से इनफ्लेशन हो। तो कम से कम प्रत्येक क्षेत्र में चाहे फैक्ट्री हो, बाबू हो, कोई भी एक ऐसी पंचवर्षीय योजना बनायी जाए जिस में एक इंडस्ट्रियल ट्रस्ट हो ताकि हड़ताल की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न मिले और सामान्य रूप से समझौते की स्थिति को लाये, उन को अधिक से अधिक सुविधायें दें। जैसे अगर पे कमीशन के अनुसार 330–550 का वेतन-मान कम है तो हम समझौते से बात करें। हड़ताल अन्तिम अस्त्र है। जब कहीं कुछ न हो तब हड़ताल करनी चाहिये। जैसा माननीय वाजपेयी जी ने कहा वहां यह कहा गया कि प्रधान मंत्री के दरवाजे खुले है न्याय के लिये। मैं साधुवाद देता हूं। वह दरवाजे सदा खुले है। इस से प्रकट होता है कि प्रधान मंत्री के प्रति लोगों में आस्था है। और क्या चाहिये आप को। यह प्रधान मंत्री के दरवाजे के अन्दर बैठने वाले ही लोग है जो यहां काम करते है, चाहे वह किसी विभाग का मंत्री हो, प्रधान मंत्री की ओर से ही वह काम करते है।

इसलिये मेरा कहना है कि जो सजा उन को दी जा रही है वह न दी जाय। जो कष्ट उन को पहुंचाया गया है उस पर सहानुभूति के साथ सोचा जाय और एक शांत वातावरण का सृजन किया जाय। क्यों कि वह लोग भी वाच डौग हैं, उन की सर्विस महत्वपूर्ण है। पी०एण्ड०सी० में आप लोग ही बैठ कर पूछते हैं कि कहिये क्या हुआ। और फिर यह संस्था भी स्वतंत्र है, राष्ट्रपति के प्रति उन का दायित्व है। माननीय वाजपेयी की भावना का समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि कोई ऐसी स्थिति न आ जाए जिस से उन का असंतोष और बढ़े।

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar): Mr. Chairman, I want to say that the behaviour of the Government against their own employees amounts to naked aggression. What happened in the office of the Comptroller and Auditor-General of India? On the 7th June 1974 there was a demonstration in a peaceful manner. In accordance with the Constitution, they have a right to demonstrate, or associate themselves with the demonstration, in a peaceful manner. Long before, they had placed before Government a charter of their demands. But the Department never cared to listen to them, never responded to their demands. Ultimately, they were compelled to demonstrate on the 7th June 1974. For that offence they were arrested under the DIR. This is gross misuse of DIR. That is why I say that this is aggression by Government against their own employees. Even though there was no violence in the office of the Auditor General at Rajkot, yet 9 employees were arrested. The charges given to them clearly state that there was no violence. Sir, with your permission I will read the charges against them, first in Gujarati langunage, and then the translation. (*Read in Gujarati*). Now I will give the English translation.

श्री एस० एम० बनर्जी : समझ गए हैं। उन्होंने कायदे का उल्लंघन किया।

SHRI P. M. MEHTA: There is no mention of violance even in the charge sheet of the Police themselves, and yet they were arrested under DIR section 119(3). The then Finance Minister, Mr. Chavan, misled the House. On 22nd August, 1974, he said in the Lok Sabha:

"On 1st May, 1974, the All India Non-gazetted Audit and Accounts Association served a strike notice on the Comptroller and Auditor General The notice was for an indefinite strike from 6.00 A.M. on 10th May 1974. It was to be preceded by a pen-down strike on 8th and 9th May.

The strike affected about 20 Audit and Accounts Offices in the country. In the offices at Rajkot and Gwalior, there was serious intimidation and violence by some of the striking employees with the consequence that

[Shri P. M. Mehta]

they were arrested by the police. The strike was withdrawn on 13th May, 1974."

This is an absolutely false statement. The incident occurred on 7th June, 1974, but the Finance Minister says that in connection with the notice of the strike and the strike the employees were arrested. The Finance Minister has not only misled the House but he has deliberately given false information. Therefore, it is the duty of this House to ask the Government that the case against these 9 employees and others pending in the courts under DIR section 119(3) should be immediately withdrawn and the Comptroller and Auditor General should be asked to give an explanation and he should be penalised.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): Let me at the outset say how much we appreciate Shri Vajpayee's bringing this motion, because without such a motion and discussion, not only these employees of the AG's office all over the country would continue to remain under a hanging sword, but the question of accountability of the Comptroller and Auditor-General to this House would also have remained unattended and unsolved. Therefore, I am very glad, and I congratulate my esteemed friend for bringing this motion.

The matter is very serious on several grounds. First and foremost, we have to decide whether the Comptroller and Auditor General of India is accountable at all, and if he is accountable because the Constitution of India says that he is accountable, then he is accountable to whom and in what manner will his action be brought to book? If this House finds that what the AG's office, and particularly the Auditor General does is something which is not in tune with his duties and obligations and rights as laid down in the Constitution, then what are we to do? There must be surely some way of bringing him to book.

Of course, my hon. friend Shri Banerjee read out the Constitutional provisions. Articles 148 to 151 make mention of the functions of the Comptroller and Auditor-General of India, but nowhere does it mention that the Auditor General has such wide powers of doing whatever he likes irrespective of what happens in the other parts of the Government and public sectors in regard to dealing with the employees of his department. Therefore, where does he get these powers? Surely, he does not get this power from the Constitution; he does not get this power from the general practice obtaining in this country.

Sir, as a matter of fact, it is a well established principle and a well established practice in all democracies, and I would say in all civilized and progressive countries of the world, that employees have a right to come together, form unions, establish consultative machinery with the employers and go on getting their grievances redressed.

If the AG's office does anything which comes in the way of this normal practice of trade union activities is it really permissible and if it is not permissible can we keep quite and can we show a posture of helplessness? All these months I am afraid we are having a posture of sheer helplessness although we call ourselves, this Parliament, supreme, not sovereign, but supreme in many respects. This House and this Constitution which is soverign by which we govern, cannot take any action against this kind of intimidation, which really is not an intimidation by the employees on the AG, but by the AG on the employees. It is the other way round. Therefore, this high-handedness, this arbitrary action, this cavalier fashion in which AG and his senior colleagues are behaving with the vast number of employees must be put to an end. Therefore, I must really spell out this important implication of the whole matter. It is not a question of some few hundreds or some few thousands employees of this

country who are in distress; it is a question of certain fundamental principles of democratic functioning which are involved in this.

Therefore, I want to know from the hon. Minister what is the Government's attitude in general towards trade union activities? Are they going to tell us that they will not have any legitimate trade union activities in their public sector, in the Government departments? I am sure, he will say, "no, no, the attitude of the Goverment is very good and sympathetic." If he means sympathy by taking absolutely an uncalled for action against the employees whose only fault was that either they were fighting for their own demands or they were expressing sympathy for their fellow brethren in other walks of activities whether it is railway or other governmental activities—then I am sorry, this House cannot tolerate it. Therefore, I want to say that all this intimidation, thereats, suffocation, which are being experienced by these employees are something which this House cannot tolerate even for a minute.

I do not want to repeat the grounds which have already been covered very ably both by Shri Vajpayeeji and my friend, Shri Prasannabhai Mehta, when they talked about what happened in Rajkot. I also know because I met these people, not once, but several times. But I am quite sure of the fact that even the police did not say that these employees committed any act of violence But the action taken against the employees on the charge was that they committed an act of violence. This is a strange way of behaving. When the Government's own machinery—the police says that the employees have not done any violence and the AG's office says that violence has been committed, I want to tell the Minister that it is not good on their part to say so.

Shri Chavan gave an answer, when he was the Finance Minister, which was not only inadequate and incomplete, but was very misleading, far from truth. But like the employees in Rajkot office and elsewhere, either in Trivandrum or in Gwalior and other places; what did they do? After all, they were on a token strike, on a pen-down strike, on a short duration strike, which was in nuture of registering a protest and to express sympathy with other striking people or other striking brethren.

Mr. Chairman, just now, you are acting in the capacity of a Chairman. But you are also a very well-known trade unionist. You are very much concerned with the problems and rights and welfare of the labourers and workers in the whole country. I am quite sure, therefore, you will agree with me when I say that it can never be considered a crime, much less a sin, for one set of employees to do something by way of expressing sympathy with other sets of employees. After all, the workers of this unit or that unit, ultimately, all belong to the same fraternity. They are all wage earners and they all have certain common goals, certain common ideals and certain common programmes of action.

18 hrs.

How is it that the Auditor General took a series of unfortunate, extraordinary and terribly oppressive measures against these employees? My hon. friend, Shri R. S. Pandey, was saying that, after all, they are *Babus*; now, Sir, the *Babus* cannot make a revolution in terms of destroying the State and removing the Government by violent means All that the *Babus* can do is to go on strike. That is what they did. But what did the Government do in return? They used DIR. Have you enacted the Defence of India Rules for the defence of A.G. against their own employees? What is the idea?

This continued hanging sword on these unfortunate fellow citizens is a very serious matter. You will be shocked to know the steps taken by the A.G. against these employees, Mr.

[Shri P. G. Mavalankar]

Vajpayee has already given the figures: 48 dismissed, 72 suspended and 12,000 having a break-in-service including cut in Salaries Pay. And, Sir, about these 12,000 people, look at the treatment meted out to them. I would like to read out, (1) they are debarred from appearing in the departmental examination; (2) they are superseded in promotions; (3) they are not allowed to cross the Efficiency Bar; (4) they are not considered for sending on deputation; and (5) they are not allowed to appear in any all-India competitive examination or in interviews for any higher post in any of the departments.

I would like to ask, Is this democracy or is this nothing but short of high-handed dictatorial, authoritarian, totalitarian, regime? What are we in for? I want to conclude by saying that the Government must take not only an earnest and sympathetic and just view in the matter but, after what they have done with regard to Railway employees, with regard to Dockyard employees, and the like, they must take a very immediate, concrete and realistic view of the whole matter and see to it that they create a climate of goodwill so that no further ill-will, no further bitterness, continues. After all, in the interest of efficiency of the A.G.'s departments all over the country, this should be done Let the Government take immediate steps to ensure justice, to create goodwill and to create a climate of normalcy back into these departments and withdraw all the cases, wrongly and falsely made against the employees of the various units of the A.G.'s office. If they do it, I am quite sure, they will have helped in restoring normalcy. But if the Government does not see reason and does not make amends, I dare say they will have to face the dire consequences

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, माननीय बाजपेयी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करते हुए यह निवेदन करूंगा कि कंट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल के कार्यालय में काम करने वाले लोगों के खिलाफ पिछले दिनों जितनी कार्यवाहियां हुई हैं, अगर वे सारी की सारी हिन्सा और तोड़फोड़ की कार्यवाही हैं, किन्तु अलहदा किस्म का आन्दोलनात्मक कार्यवाहियों के लिये हुई है, तो उनको वापस लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के लिये एक मार्ग प्रशस्त किया है।

कंट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल वाली साहब शायद अपने को इस लोक-सभा और सरकार से भी अलहदा और ऊपर शक्ति मानते है और वह यह मानकर चलते है कि वह स्वायत्त है। उनके बारे मे हम यहां बहस भी नहीं कर सकते है। यह लोक-सभा उन पर मूकदर्शक बनकर बहुत दिनों तक नहीं रह सकती, क्योंकि उनके अहमकपने के किस्से एक कार्यालय मे नहीं बल्कि सभी कार्यालयों में सुनने को मिलते है। उनकी वजह से जितने दूसरे बड़े अधिकारी है, उनके भी दिमाग बिगड़ते जा रहे है।

राजकोट और ग्वालियर के किस्से आपको सुनने को मिले है। यह भी सुनने को मिला है कि 12 हजार कर्मचारी है जिनकी सेवाओं में भंग किया गया है लेकिन अभी तक उसको खत्म नहीं किया गया है। मैं इलाहाबाद का केवल एक किस्सा बताना चाहता हूं। वहां के ए० जी० जोयरय साहब है। आपकी ही पार्टी के माननीय सदस्य श्री छंटेलाल जी, आज के 15 दिन पहले उस दफ्तर के सामने गये क्योंकि वहां के कुछ लोग भूख-हड़ताल कर रहे थे। मुझे वहां बताया गया कि श्री छंटे लाल जी उनके दफ्तर के सामने 3 घंटे तक बैठे रहे और उन्होंने उनको इन्टरव्यू की इजाजत नहीं दी। इससे पता चलता है कि कितना ए० जी० का दिमाग बिगड़ गया। यह सही है कि

छोटेलाल पहले संसद् सदस्य नही थे, उस दफ्तर के बाबू थे । लेकिन इस वक्त तो वे संसद-सदस्य थे । इसलिये ए० जी० का इतना दिमाग बिगड़ गया है कि वे बार छोटेलाल तीन घंटे तक बैठे रहे, उनको इंटरव्यू तक नही दी गई । मुझे बाबू लोगो ने कहा कि अगर तुम होते तो दो मिनट नही बैठते उनका पर्दा उठाते और भीतर चले जाते । तो छोटेलालजी का बहुत बड़ा अपमान हुआ ।

ए० जी० आफिस के बाबू लोगो की जो ब्रदरहुड एसोसिएशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी कृपासिंह श्रीवास्तव है । उनको जयरथ साहब ने मुअत्तिल कर दिया । मुझे ए० जी० आफिस से खबर मिली कि दफ्तर मे पुलिस और पी० ए० सी० के जवान गये है, तो मै वहा गया । बाबू लोगो ने कहा कि देखो, यह पुलिस आई है । तो हमने कहा कि जब तक आपका और ए० जी० का झगड़ा रहेगा, मै बीच मे नही आऊगा, लेकिन चुकि सरकार ने पुलिस को भेज दिया है, इसलिये मेरा काम हो गया है और मैं यहा आऊगा और दखल दुगा । बहुत समझाने बुझाने के बाद किसी तरह से पुलिस गई और झगड़ा खत्म हो गया । जयरथ साहब ने हमारे सामने कहा कि ये दफ्तर के बाबू लोग काम नही करते है, बल्कि बैठ कर कागज की गोली फैका करते है । उन्होने यह भी कहा कि आप जितने चिन्तित है इनके बारे मे, और समझते है कि इनकी हालत खराब है, असल मे इन लोगो की हालत हमारे से भी अच्छी है । तो मैने जयरथ साहब से यही कहा था कि अगर इनकी हालत बेहतर है तो तुम बाबूगरी क्यो नही कर लेते, अपने दफ्तर मे अफसरी क्या कर रहे हो ?

आज हालत यह है कि जो जितनी ही बड़ी कुर्सी पर रहता है, वह अपने से छोटे लोगो को समझता है कि हमसे बेहतर हालत मे है । बड़े अफसर समझते है कि बाबू हमसे अच्छे है, बेहतर हालत मे है और बाबू समझते है कि चपरासी की हालत हमसे बेहतर है । इस समय हिन्दुस्तान की नौकरशाही को यह रोग लगा हुआ है ।

जयरथ साहब ने भी यही कहा । कृपाशंकर श्रीवास्तव आज भी मुअत्तिल है । अन्दर हाल के दौरान समय न । बल इस बात पर हो सका कि यह मुअत्तिल है यह केवल दफ्तर मे ब्रदरहुड के कार्यालय के भीतर ही जा सकते है । उसके अलावा ये दफ्तर के भीतर नही घुस सकते । लगातार पुलिस का पहरा वहा पर रहता है । यह वहा की एक मिसाल मैने दी है ।

बाजपेयी जी ने राजकोट, ग्वालियर आदि कई जगहो के बारे मे बताया है । मैं चाहूंगा कि आप इस पर गंभीरता के साथ गौर करे । जैसे श्री राम सहाय पाडे ने कहा कि ये बाबु लोग हडताल करेगे तो हद से हद कलम-पटक हडताल करेगे । मै कहना चाहता हू कि अगर इस पर आप गम्भीरता के साथ विचार नही करते है तो ये बाबु केवल कलम-पटक आन्दोलन तक न रहकर, ये कही सरकार-पटक आन्दोलन तक न पहुच जायें ।

इन्ही शब्दो के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूं ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Chairman, Sir, I share the concern of Mr. Atal Bihari Vajpayee and other hon. members who have made their observations on this particular problem. So far as the issues are concerned, there are four salient features, first, withdrawal of the police cases, second, break in service, third, pay cut; and fourth, derecognition for the Association. These are the four major issues ...

AN HON. MEMBER. Suspension and termination also.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE. I have said, break in service. Of course, termination means permanent break in service. Anyway, these

[Shri Pranab Kumar Mukherjee]

are the points which have been highlighted by the hon. members, and certain points have been referred to incidentally. One thing I would like to make quite clear. It is neither our intention nor is it the intention of the Comptroller and Auditor-General to do what has been described as high-handedness and oppression. In fact, the circular detailing the manner in which the striking employees were to be dealt with was applicable to all Government employees except the Railways which were treated slightly differently and for reasons the hon. Members themselves are aware of Therefore, it is not a fact to say that employees of the C&AG offices have been treated absolutely on a different footing and have been discriminated against the general principle which has been applied to all other Government employees belonging to Posts and Telegraphs and others.

Regarding the withdrawal of the cases, it has been pointed out on earlier occasions also on the floor of the House that where there is a definite charge of violence such as intimidation and instigating others to take part in the strike, only in those cases, the Police cases should be pursued. Otherwise, if I remember correctly, on 30th May itself, instructions were issued to various competent authorities at the lower administrative level to review these cases and see that these are not being applied universally on all striking employees . . . .

SHRI S. M. BANERJEE: May I ask you one thing? Withdrawal of cases may be there. But why should they be suspended?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: I am coming to that. I have noted all the points.

It is necessary to understand that it is not directly under the administrative control of the Finance Ministry though we are accountable partly for its functioning. Practically, the C&AG is accountable to the Parliament to some extent so far as his services and other things are concerned through the Ministry of Finance, but, he enjoys a constitutional position as has been highlighted by the hon. Members themselves. Therefore, I would like to submit my observations and would like to clarify the position as it is to-day.

Regarding the break in service also, the same principle has been applied and in fact, when these issues came before the government. In fact the striking employees are divided into categories: (1) belonging to the aggressive categories and (2) employees belonging to the submissive categories who merely complied with the call of the strike Therefore, in all these cases, for the time being, action was taken against them. Certain penalties were imposed. But, later on, at a subsequent stage, after review, it was withdrawan. If I quote some of the figures, you yourself would come to the conclusion that it is not a fact that the Government has not taken any action and has not reviewed the position.

Regarding the number of employees arrested by the Police against whom cases are pending in the courts, it was originally 57. Now it has come down to 53—of course, not much, because of reasons I have already mentioned Here in this case I would like to have one clarification from Mr. Vajpayee. While replying to the discussion, he can give it. Someone has quoted a charge-sheet from the Police. There he says that the Police had nothing to complain against the employee Here I would like one point to be clarified. It is for the Police to take action for violent activities. If Police people do not find anything violent against the man, how the man can be prosecuted against? I would like it to be clarified on this point and I would like to know what the position is. So far as the employees under suspension are concerned, I have said, this number which was over hundred on 30th April has come down

to 77. We have issued instructions saying that in those cases where intimidation and other types of violence and violent activities were indulged in, they should be caught, and if there were specific charges against them, they should be prosecuted. Regarding the number of employees whose services were terminated originally this was 96 and now it is 91 and regarding number of employees whose pay was cut, instead of 7180, now it is 6571, and in regard to number of employees in whose cases break in service was ordered, instead of 3636 it is now 2236. And regarding the court cases by the employees against the termination order or suspension order, that does not affect the position, so far as the present discussion is concerned. And, I may say clearly, it is not a fact that Government has taken a rigid attitude, or that they are sitting tight over it. It is not at all correct. The hon. Member asked regarding pay-cut why for three days, pay cut was ordered. It is not correct to say, this was a token strike for 10th alone. When the strike notice was given that notice was given for an indefinite strike. It said so. And it started from the 10th. 11th was Second Saturday; 12th was Sunday, if I remember correctly. And they resumed duty on the 13th Monday. So, it is not a fact that it was only a token strike for one day on 10th only. The notice of strike was for an indefinite period. I may repeat it, the notice was for an indefinite period. But the strike fizzled out. That is also the position.

SHRI S. M. BANERJEE: Shri Morarji Desai said he is going on indefinite hunger-strike. This indefinite hunger strike is also broken. The strike was withdrawn. How could it be indefinite strike when holidays are intervening?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: We have ideas about indefinite strike and definite strike and strike usually does not come to an end in one day and Mr. Banerjee knows much better than I do and when I was almost a school-boy he had so many indefinite strikes and so many definite strikes. The strike notice said indefinite strike. It was not as if it was one day's token strike.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: They gave notice for indefinite strike but it is also a fact that they withdrew the strike by sending timely intimation to the Government saying that they are going back to their services.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: They could not have done it earlier on 11th and 12th—they were holidays—even if they wanted to go they could not have come holidays. So, first opportunity was on 13th.

MR. CHAIRMAN: On those days Government would not have known whether the strike was indefinite or not

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Now they know.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE. My point is this.

Regarding the break in service and suspension also, the points related only to the aggressive strikers in that State Let us come to the bigger question as to what should be our attitude now. It has been pointed out while replying to the questions on earlier occasions that the case was not closed. So far as derecognition is concerned, Shri Vajpayee and hon. Members are aware that the association has not been derecognised. The notice has also not been withdrawn. Ultimately, it was decided at a certain stage by the Cabinet—the Cabinet instructed the Minister in charge of the Department of Administrative Reforms and Personnel—that they should start dialogue with the employees. That discussion will take place. When it takes place, it would not be confined only to the issue of recognition or derecognition but also to the issue of having joint consultative machinery and other issues. I hope that will give us an opportunity to review all other cases in which we can take an overall view of the situation.

[Shri Pranab Kumar Mukharjee]

It is not possible for me just at the moment to commit what type of decision Government can take. But, we expect that if a dialogue starts or if we initiate a discussion, it would be possible for us to come to a decision.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Let us know when that dialogue will take place.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE. That will start very soon. That I can tell you. We can say that we can discuss the problems across the table and many of the problems could be sorted out during discussions.

The last point which Mr. Mehta and Shri Mavalankar mentioned was about Shri Mavalankar mentioned was about the House by Shri Y. B. Chavan when he was Finance Minister. Sir, it is not a misleading information. So far as clarification is concerned, I am explaining it.

SHRI S. M. BANERJEE· He has been removed from that Ministry only because of this!

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE· The position is this. When actually arrests and other actions took place, it was on the 7th June and not in the month of May—on 10th That was in connection with action that took place on 10th of May. Therefore it was a continuation of the action. The 7th June and the earlier incidents are as a consequence of the strike of 10th May and subsequent action taken. If he says that action taken on 7th June was a continuation of the action of 10th May and tries to emphasise it to be so, I say that it is an action in chain· it is not an isolated one. 7th June is not an isolated incident.

I hope I have covered all the points which the hon. Members have raised.

SHRI P. M. MEHTA. Because the service of one employee was terminated, the minds of other employees were agitated.

श्री अटल बिहारीवाजपेयी (ग्वालियर): सभापति जी, मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध डी० आइ० आर० के अन्तर्गत केसेज चलाये जा रहे है, वे केसेज राज्य सरकारें चला रही है और राज्य सरकारों ने अलग अलग नीतियां अपनाई है। रेल्वे कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों को कुछ निदेश दिये गये थे, क्या इन कर्मचारियों के बारे में कोई निदेश नही दिये गये ? डी० आइ० आर० के अन्तर्गत केस चले या न चले—इस का निर्णय कौन करेगा, क्या राज्य सरकारों पर छोड दिया जायेगा ?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE I clarified the position that so far as the Audit and Accounts department's employees are concerned, they are treated on par with the other Government employees and not with the railway employees. They have been treated separately.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण किया है, उस के बाद भी स्थिति स्पष्ट नही हुई ...

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : और ज्यादा धूमिल हो गई है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन मैं दो तीन बाते कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि मंत्री महोदय ने जो घोषणा की है कि काम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जैनरल से कहा गया है कि वे कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता आरम्भ करें । इस का मैं स्वागत करता हूं—देर से सही, लेकिन एक ठीक कदम उठाया गया है । परन्तु इस बात का स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया कि यह वार्ता बन्द क्यों की गई थी ? 1968 से यहां डिपार्टमेन्टल कान्सिल और ज्वाइन्ट कन्सलटेटिव मशीनरी काम नही कर रही हैं। क्या यह काम्पट्रोलर एण्ड आडिटर

जैनरल के अधिकार में है कि वे जब चाहें कर्मचारियों से बात करें और जब चाहें बात बन्द कर दें ? क्या बात शुरू करने के लिए कैबिनेट तक जाना पड़ेगा । अभी भी वे नही बता सके है कि बातचीत कब से शुरु होगी । लेकिन हम आश्वासन चाहते है कि अन्य विभागों की तरह से ए० जी० आफिस के कर्मचारियों के लिये ज्वाइन्ट कन्सलटैटिव मशीनरी और डिपार्टमेन्टल कान्सिल को फिर से चालू किया जायगा। इस तरह का आश्वासन आना बहुत जरूरी है ।

मंत्री महोदय ने कहा कि चार्जशीट अदालत में नही है तो फिर कर्मचारियों पर मुकदमा कैसे चल सकता है । सभापति जी आप स्वय वकील है आप जानते है कि मुकदमा दायर हो सकता है, कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता सकता है — चाहे बाद में अदालत उसक, भले ही रिहा कर दे । लेकिन तारीखे पड सकती है कर्मचारी परेशान हो सकते है अदालत में उन को घसीटा जा सकता है ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता ने जो चार्जशीट पढ़ कर सुनाई, उस की कापी मेरे पास भी है । पुलिस कही नही कहती कि राजकोट में कर्मचारियों ने कोई हिंसा की। उन का इतना ही कहना है कि उन्होंने नारे लगाये। पुलिस तो वहां आने को भी तैयार नही थी,. लेकिन इन के आफिसर महोदय खुद थाने गये, कर्मचारियों के विरुद्ध डी० आई० आर० का मामला दर्ज करने के लिये पुलिस को मजबूर किया। चूंकि मामला डी० आइ० आर० में दर्ज हुआ था इस लिये उन को सर्विस से सस्पेण्ड कर दिया गया । अब भले ही केस अदालत में चले और बाद में रद्द हो जाय, लेकिन आज जो विकटिमाइजेशन हो रहा है उस का इलाज क्या है ? मैं यह चाहता हूं कि आप जरूर डायलोग कीजिये, लेकिन काम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जैनरल को यह कहा जाना चाहिये कि वे हर मामले पर सहानुभूति के साथ विचार करें ।

एक प्रश्न जो मैं पहले नही उठा सका , उस की ओ अब आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ कर्मचारी टेम्परेरी थे, उन की सर्विसिज को टर्मिनेट कर दिया गया, अब उन का कोई पूछने वाला नही है। वे अपना दुखड़ा किस के सामने रोये । उन्होंने हड़ताल में भाग लिया था—यह ठीक है .....

श्री एस० एम० बनर्जी : उन का दुखड़ा मिनिस्टर सुन सकते है, जिन की सर्विस भी ऐसी ही है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप ठीक कर रहे है । सभापति महोदय मैं चाहता हूं कि जब सभी कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जा रहा है तो उन में जो ऐसे कर्मचारी थे, जो टैम्परेरी थे जिन को आप एक महीने के नोटिस पर निकाल सकते है . ....

श्री दिनेन भट्टाचार्य : बहुत से गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स तो सालों से टेम्परेरी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी . सी० पी० डब्लू० डी० और रेल्वे में तो 27–27 साल से कर्मचारी टेम्परेरी चल रहे हैं रिटायर होने के समय तक भी टेम्परेरी ही रहते हैं । ए० जी० आफिस में भी ऐसे कर्मचारी थे जो अस्थायी थे और जिन्हे नौकरी से निकाल दिया गया , आज उन के मामलों पर कोई भी विचार करने को तैयार नही है । मैं आशा करता हूं कि जब बात चीत चलेगी तो कर्मचारियों के प्रतिनिधि इस मामले को उठायेंगे, इस

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

लिये आप कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल से कहें कि वे इस में सहानुभूति का रवैया अपनायें।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन को एक बार यहां भी बुलाइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि रेल्वे कर्मचारियों का मामला अलग है और बाकी के सब कर्मचारियों के लिये जो आम हिदायतें दी गई हैं वे ए० जी० कर्मचारियों के आफिस पर भी लागू होंगी। श्री बनर्जी ने अभी बतलाया था कि इन्कम टैक्स में 5 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई थी, पी० एण्ड टी० में 40 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई थी. प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी में 22 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई थी, सब को वापस ले लिया गया। अगर रेल्वे कर्मचारियों को आप छोड़ भी दें तो पी० एण्ड टी०. इन्कम टैक्स. प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी डिपार्टमेन्ट के जो कर्मचारी थे, उन को वापस ले लिया गया तो क्या कारण है कि ए० जी० आफिस के कर्मचारियों को वापस न लिया जाय। इस का मतलब है कि समान भूमिका नहीं है और यदि है तो कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जैनरल उस का पालन नहीं कर रहे हैं।

मंत्री महोदय का यह कहना काफी नहीं है कि हमारा इरादा अच्छा है हमें इरादे को नहीं देखना है. हमें आचरण को भी देखना है। इरादे नेक हैं, अगर आचरण दोषपूर्ण है तो कर्मचारियों को राहत नहीं मिल सकती। मेरा निवेदन है कि जो भी हिदायतें जारी की गई हैं, वे कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जैनरल के कार्यालयों में ठीक तरह से लागू हों—इस आधार पर हम को देखना होगा।

मंत्री महोदय ने ग्रे-कट का मामला उठाया उन का यह कहना ठीक है कि और मैं इस से इन्कार नहीं कर सकता कि वह इन्डेफिनिट स्ट्राइक का नोटिस था, लेकिन तारीख 13 को नोटिस वापस ले लिया गया। अब सरकार को लीनियन्ट व्यू लेना चाहिये। ता० 11 और 12 को छुट्टी थी, कर्मचारी यदि चाहते तो भी काम पर वापस नहीं आ सकते थे, दफ्तर बन्द थे . .

श्री एस० एम० बनर्जी: छुट्टी के दिन जाते तो गिरफ्तार हो जाते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गिरफ्तार नहीं भी होते तो भी वे काम नहीं कर सकते थे। इस लिये अब उन्होंने देखा कि हड़ताल को ज्यादा समर्थन प्राप्त नहीं है और हमारी भी उन को सलाह यही थी कि आप ने हड़ताल कर के अच्छा नहीं किया, तो अब ता० 11 और 12 की तनख्वाह उन्हें वापस दे दी जाय। परसनल डिपार्टमेन्ट ने इन्कम-टैक्स वालों से पूछा था, तो यही क्लैरिफिकेशन किया गया कि ता० 11 और 12 की तनख्वाह डकम नहीं की जानी चाहिये। इस पर आप जरा उदारता से विचार करें और कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल को कहें

कि वे अपना रवैया बदलें। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए पार्लियामेंट हाउस वे आया करते हैं।

सभापति महोदय : 13 को जब उन्होंने वापस लिया तो उस में क्या उन्होंने यह कहा कि हम यह 11 से वापस ले रहे हैं? या क्या कहा. 10 से वापस ले रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 10 को हड़ताल हो चुकी थी। आप तो कानून वाली बात कर रहे हैं। वह कह भी देते कि 10 से वापस ले रहे हैं तो 10 तो बीत चुका था। अब तीर निकल चुका है इस लिए 11-12 के बारे में सहानुभूति के साथ विचार होना चाहिए।

18.31 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, May 9, 1975/Vaisakha 19, 1897 (Saka).

GMGPND—M—737/L.S.—26-6-75—978.